केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क- bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 53 शनिवार 12 सितम्बर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

मंदिर से चोरी का खुलासाः २ गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
हर्रैया (बस्ती)। हर्रैया पुलिस ने प्रसिद्ध कोहले समय माता मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से करीब 23 किलो पीतल के घंटे और घंटियां, दो दानपात्र, पांच पीतल–तांबे के लोटे और 2,342 रुपए बरामद किए गए हैं। हालांकि, चोरी का मुख्य सरगना पुलिस की घेराबंदी के दौरान भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने शुक्रवार को बताया कि थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। 10 सितंबर की रात करीब पौने 12 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि एसबी एकेडमी के पास एक निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में कुछ संदिग्ध लोग चोरी का सामान बांट रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की।

पुलिस के मुताबिक, घेराबंदी के दौरान भाग रहे रोहित शर्मा (22), निवासी एकडंगी और सुभाष गिरी (32), निवासी गोसाईं पुरवा को पकड़ लिया गया। वहीं, गैंग का मुख्य सरगना बताए जा रहे कुश गिरी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल करीब 23 किलो पीतल का सामान बरामद किया। इसमें एक बड़ा घंटा 11.55 किलो, आठ मध्यम घंटे 6.20 किलो और 22 छोटी घंटियां 5.30 किलो शामिल हैं। इसके अलावा दो दानपात्र और पांच पीतल, तांबे के लोटे भी बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, बरामद रकम में दानपात्र से मिले 1,342 रुपए और आरोपियों के पास से मिले 1,000 रुपए शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 2 सितंबर को कोहले समय माता मंदिर से दानपात्र और लोटे चोरी किए थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने थानेश्वर मंदिर समेत अन्य जगहों से भी घंटे चोरी किए थे।

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि करीब 20 तांबे–पीतल के लोटे उन्होंने हाइवे पर ट्रक चालकों और राहगीरों को बेच दिए थे। इनसे मिले पैसों में से बचे 1,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, चोरी का सामान एकडंगी गांव में पंचायत भवन के पीछे झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाध्यक्ष संजय कुमार, उपनिरीक्षक कामेश्वर मिश्रा, दिनेश कुमार सिंह, सुरेंद्र यादव, मुख्य आरक्षी वरुण राय, दीपराज यादव, आरक्षी धर्मेंद्र यादव, अभिषेक वर्मा और आर्यप्रताप सिंह शामिल रहे।

दिव्यांग पेंशन की नई व्यवस्था से राहत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। दिव्यांग पेंशन के भुगतान की व्यवस्था बदल दी गई है। अब पेंशन का भुगतान एसएनए–एसीआरएसएच (समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण) के जरिए होगा। इस नई व्यवस्था से जिले के 15,368 दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। लंबित पेंशन के भुगतान का रास्ता भी साफ होने की उम्मीद है।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी तनुज त्रिपाठी ने बताया कि जिले में कुल 15,368 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें से 11,841 लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत से कम है। इन लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026–27 की अप्रैल, मई और जून की पहली तिमाही की किस्त के रूप में तीन हजार रुपये जुलाई में मिल चुके हैं।

ब्रिक्स देशों में दुनिया की आधी आबादी- मोदी

नई दिल्ली (आभा)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बैठक के बाद दोनों नेताओं ने बयान जारी किए। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की आधी आबादी है। इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब ढाई गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कम्बाइंड जीडीपी साढ़े चार गुना हुई। यानी कि ब्रिक्स की इकोनॉमी दो गुना रफ्तार से बढ़ी है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत ग्रोथ का भरोसा दे रहा है। हम एयरपोर्ट, रेलवे आदि का तेजी से विकास कर रहे हैं। साथ ही, सेमीकंडक्टर, बायोटेक आदि क्षेत्रों में में नई क्षमता विस्तार कर रहे हैं। आज भारत में स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। दो लाख से अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।

बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'जैसे ही ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में जा रहा है, मैं ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल से कहना चाहूंगा कि क्या आप ब्रिक्स देशों के बीच टॉप दस ट्रेड बैरियर हटाने पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं? क्या हम हर साल 100 ब्रिक्स स्टार्टअप्स को दूसरे ब्रिक्स मार्केट में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं? क्या हम अपने बिजनेस के बीच एक हजार नई पार्टनरशिप बना सकते हैं? हमें हर साल इन तीन पैरामीटर पर अपनी प्रोग्रेस का रिव्यू करना चाहिए। आइए ब्रिक्स के एम्बिशन को एक्शन में और अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को ग्लोबल सॉल्यूशन में बदलें। ब्रिक्स को आगे बढ़ने दें और दुनिया को भी आगे बढ़ाएं।'

भागवत शुक्ल अध्यक्ष, सन्तोष त्रिपाठी महामंत्री निर्वाचित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ शाखा बस्ती के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के चुनाव शुक्रवार शाम करीब 5 बजे संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर भागवत शुक्ल ने जीत दर्ज की। उन्हें 112 वोट मिले। अशोक कुमार सिंह को 79 और राजेंद्र कुमार को 1 वोट मिला। उपाध्यक्ष पद पर वीरेंद्र कुमार चौधरी 96 वोट पाकर विजयी हुए। उनके प्रतिद्वंद्वी दीपक श्रीवास्तव को 53 और मनोज कुमार को 49 वोट मिले। सचिव/महामंत्री पद पर संतोष त्रिपाठी ने 101 वोट पाकर जीत दर्ज की। चंद्रमोहन श्रीवास्तव को 46 और राधेश्याम सिंह को 45 वोट मिले।

संयुक्त सचिव पद पर रोहित जायसवाल 110 वोट पाकर विजेता बने। उनके सामने नीरज कुशवाहा को 82 वोट मिले। क्रीड़ा सचिव पद पर जैनेंद्र कुमार और संगठन सचिव पद पर सालिक राम यादव निर्विरोध चुने गए। चुनाव अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय आशुतोष मणि त्रिपाठी, चुनाव पर्यवेक्षक सुधीर श्रीवास्तव, सहायक चुनाव अधिकारी द्वितीय लिपिक अमित कुमार श्रीवास्तव, विनय तिवारी और गौरव यादव ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। एडवोकेट संदीप कुमार, अरुण श्रीवास्तव, नियाज अहमद, जीतेंद्र कुमार, राधेश्याम सिंह, आदर्श श्रीवास्तव और चंद्रशेखर यादव समेत कई लोगों ने विजेताओं और उपविजेताओं को बधाई दी है।

लंगूर बंदरों के आतंक से मिली राहत, मनोज चौधरी ने पकड़वाकर वन विभाग को सौंपा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। रुधौली विकासखंड क्षेत्र के सुरवार, रमवापुर, बिजहरडूहा, टिकरी, ढोढऊपार सहित दर्जनों गांवों में लंगूर बंदरों के आतंक से ग्रामीण लंबे समय से परेशान थे। बंदरों के झुंड से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों के अनुसार, बंदरों के हमले में करीब 20 लोग घायल भी हो चुके हैं।

बंदरों के बढ़ते आतंक से परेशान ग्रामीणों ने इसकी सूचना रुधौली विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी मनोज चौधरी को दी। ग्रामीणों की समस्या की जानकारी मिलते ही मनोज चौधरी ने तत्काल बंदर पकड़ने वाली टीम को बुलवाया। टीम ने अभियान चलाकर आतंक का कारण बने लंगूर बंदरों को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें संबंधित विभाग को सौंप दिया गया।

समाजसेवी मनोज चौधरी ने कहा कि ग्रामीणों की ओर से उन्हें लगातार बंदरों के आतंक की सूचना मिल रही थी। लोगों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने तत्काल पहल करते हुए बंदरों को पकड़वाने की व्यवस्था कराई। उन्होंने कहा कि लंगूर भी जीव हैं, लेकिन आबादी वाले क्षेत्रों में उनके रहने से ग्रामीणों को परेशानी और खतरा पैदा हो रहा था। अब संबंधित विभाग इन्हें उनके अनुकूल सुरक्षित स्थान और जंगल क्षेत्र में पहुंचाने की कार्रवाई करेगा। लंगूर बंदरों के पकड़े जाने के बाद प्रभावित गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए मनोज चौधरी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए समय पर की गई इस पहल से उन्हें काफी राहत मिली है।

किराये पर दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना का घर, हियुवा नेता ने किया डीएम से जांच, कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। हिन्दू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री विनय सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र देकर कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा पतेलवा वार्ड नं. 24 में एहसानुल्लाह पुत्र रहमतुल्ला और नियाज अहमद पुत्र रहमतुल्ला द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घर पर किराये पर देने की जांच और कार्रवाई की मांग किया है।

डीएम को दिये पत्र में हिन्दू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री विनय सिंह ने कहा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा पतेलवा वार्ड नं. 24 में एहसानुल्लाह पुत्र रहमतुल्ला और नियाज अहमद पुत्र रहमतुल्ला द्वारा तथ्यों को छिपाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घर पर को किराये पर देकर किराया ले रहे हैं। एहसानुल्लाह पुत्र रहमतुल्ला और नियाज अहमद पुत्र रहमतुल्ला सम्पन्न व्यक्ति हैं। दोनों के पास दो मंजिला मकान हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री योजना के तहत एहसानुल्लाह और नियाज अहमद पुत्रगण रहमतुल्ला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लिया और निर्मित घर पर को किराये पर देकर किराया ले रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग किया है।

कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटेगी भाजपा, सर्वे के आधार पर नये चेहरों को मिलेगा मौका

संवाददाता– गोरखपुर।
प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। प्रदेश में जीत की हैट्रिक को लेकर शीर्ष नेतृत्व कई राउंड में आंतरिक सर्वे करा चुका है। ताजा सर्वे में गोरखपुर क्षेत्र के कई सीटिंग विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं मिला है। ऐसे में इनका टिकट कटने की अटकलें लगने लगीं हैं। वहीं, 17 सितंबर से महीने भर चलने वाले सेवा संकल्प अभियान में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के आने की चर्चाओं ने विधायकों की नींद उड़ा रखी है।

गोरखपुर क्षेत्र में 10 प्रशासनिक और 12 संगठनात्मक जिले आते हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने न सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के दोहराने के साथ ही इसे बेहतर करने की चुनौती है। पिछले विधानसभा चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा में 42 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। वहीं, लोकसभा की 13 सीटों में 6 भाजपा के पास है। पिछले अनुभव बताते हैं कि भाजपा की स्थिति भले ही गोरखपुर–बस्ती मंडल में ठीक रही हो लेकिन मऊ, आजमगढ़ और बलिया में अच्छी नहीं थी।

आंतरिक सर्वे में साफ हुआ है कि सीटिंग 42 विधायकों में 15 से अधिक विधायकों की रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। पार्टी के जानकार बताते हैं कि सर्वे में लाभार्थी योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थितियां ठीक हैं, लेकिन विधायकों के प्रदर्शन के स्तर पर लोगों में आक्रोश दिख रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी चेहरों को बदल कर लोगों के गुस्से को कम कर जीत सुनिश्चित करना चाहती है।

पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की माने तो 17 सितम्बर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के बहाने पार्टी लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश में है। 13 बिंदुओं पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से पार्टी संदेश पहुंचाना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार में विकास के हर पैमाने पर बेहतर काम हुआ है। इन कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े जैसे दिग्गज गोरखपुर क्षेत्र में आ सकते हैं। दिग्गज नेता गोरखपुर आएंगे या फिर बलिया–आजमगढ़ इसपर स्थानीय नेता कुछ बोलने से बच रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि यूपी विधानसभा को लेकर संभावित चेहरों की तलाश को लेकर दौरे के बहाने कोशिशें जरूर होंगी।

गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा के अध्यक्ष विनोद राय ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष प्रदेश के छह क्षेत्रों में आएंगे। इन्हें गोरखपुर क्षेत्र में भी आना है।

शिक्षा मित्रों ने टीईटी परीक्षा में शामिल किये जाने की मांग को लेकर बीएसए को सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। शुक्रवार को आदर्श समायोजित शिक्षक/ शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष राम पराग चौधरी के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 147000 शिक्षा मित्रों को विशेष शिक्षक पात्रता विशेष परीक्षा (टीईटी) में शामिल कराये जाने की मांग को लेकर बीएसए को ज्ञापन सौंपा।

बीएसए को सौंपे ज्ञापन में सरकार से समायोजित शिक्षकों व शिक्षा मित्रों को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में शामिल किए जाने की मांग करते हुये कहा गया है कि शिक्षा मित्रों की सेवा नियमावली बनाये जाने और सेवा काल 62 वर्ष करने के साथ ही जनपदीय और अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया को शीघ्र पूरा कराया जाय।

ज्ञापन देने के बाद शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष राम पराग चौधरी ने बताया कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पिछले 26 वर्षो से कार्यरत शिक्षा मित्रों को इस विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया गया है। एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राघवेन्द्र प्रसाद उपाध्याय ने मांग किया कि शिक्षा मित्रों को भी इस विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल कर उन्हें समायोजन का अवसर दिया जाए।

बीएसए को ज्ञापन सौंपने के दौरान उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल, चन्द्रिका सिंह, बनकटी अध्यक्ष अभय सिंह यादव, ने कहा कि शिक्षा मित्रों की मांगे जायज है। इस संघर्ष में संघ उनके साथ हर स्तर पर खड़ा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से अनिल कुमार दूबे, विजय बहादुर यादव, अजीत कुमार चौधरी, सन्तोष कुमार शुक्ल, तुलसीराम, उमेश चन्द्र तिवारी, पंचानन पाल, बाल गोपाल शुक्ल, सन्तोष कुमार भट्ट, लालता प्रसाद, अविनाश मिश्र, दिनेश कुमार चौधरी, अजय कुमार पाण्डेय, पवन तिवारी, जालन्धर प्रसाद, अर्चना यादव, रामधनी चौधरी, पवन कुमार चौधरी, राजेश कुमार चौधरी, यशवन्त कुमार, राजेन्द्र प्रसाद, रामनयन, विजय कान्त ओझा, बालेन्द कुमार, हरीश मौर्या, अब्दुल वहीद अंसारी के साथ ही अनेक शिक्षा मित्र और विभिन्न शिक्षक संघों के पदाधिकारी शामिल रहे।

55 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का विधायक ने किया निरीक्षण, दिए निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। विधानसभा क्षेत्र हर्रैया में शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, खेल और बेहतर आवागमन से जुड़ी करीब 55 करोड़ रुपये की निर्माणाधीन परियोजनाओं का शुक्रवार को विधायक अजय सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेते हुए अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए।

– जनता के विश्वास को मजबूत करना प्राथमिकता –अजय सिंह

विधायक ने सबसे पहले थान्हा खास, हर्रैया में लगभग 4.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन आईटीआई कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि संस्थान शुरू होने से क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी और रोजगारपरक शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके बाद विधायक बीआरसी हर्रैया परिसर पहुंचे और लगभग 36 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह विद्यालय क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकासखंड परसरामपुर के ग्राम धरमपुर में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन स्टेडियम का भी विधायक ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है और यह स्टेडियम क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण मंच बनेगा। निरीक्षण के दौरान विधायक ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चल रहे संपर्क मार्गों और सड़क निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता के धन का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए और निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता में कमी स्वीकार नहीं की जाएगी। विधायक ने कहा कि हर्रैया की जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें सेवा का अवसर दिया है, उस विश्वास पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए आधुनिक विद्यालय, युवाओं के लिए आईटीआई, खेल प्रतिभाओं के लिए स्टेडियम और बेहतर आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण हर्रैया के भविष्य को मजबूत आधार देगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और उन्हें निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि हर्रैया में विकास अब केवल योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

संगिनी, आशा बहुओं ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन स्थाई कर्मचारी का दर्जा, मानदेय वृद्धि की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। शुक्रवार को आल इंडिया आशा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्तोष पाण्डेय के नेतृत्व में आशा बहुओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य चिकित्साधिकारी को ज्ञापन देकर संगिनी एवं आशा बहुओं को स्थाई कर्मचारी का दर्जा, स्थाई वेतन, मानदेय तथा अनिवार्य रूप से आयुष्मान कार्ड, कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग किया।

–संगिनी, आशा बहुओं का बढे मानदेय, मिले कैशलेश चिकित्सा सुविधा–सन्तोष पाण्डेय

ज्ञापन देने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्तोष पाण्डेय, राष्ट्रीय महासचिव शैलेन्द्र श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष इशरावती चौधरी ने कहा कि संगिनी एवं आशा बहुएं दिन–रात चौबीसों घंटे स्वास्थ्य विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर–घर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, बावजूद इसके इन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा या सुविधा नहीं दी जाती। संगठन ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान भी आशा बहुओं ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें सुरक्षा किट तक उपलब्ध नहीं कराई गई। संगठन ने यह भी कहा कि सबका आयुष्मान कार्ड बनवाने वाली ये कार्यकर्ता खुद इस सुविधा से वंचित हैं।

ज्ञापन में संगिनी को 30 हजार रुपये तथा आशा बहुओं को 24 हजार रुपये मानदेय देने और इनकी स्थाई नियुक्ति करने की मांग की गई है। चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी न होने पर संगठन आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होगा।

ज्ञापन सौंपने वालों में इंद्रावती देवी, नीलम, फुलवासा, विन्दू देवी, सुनीता देवी, पूनम सिंह, कुसुम देवी, सुमन यादव, गीता देवी, सुनीता दूबे, ममता पाण्डेय के साथ ही प्रेमशंकर पाण्डेय और आशा बहू शामिल रहीं।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 12 सितम्बर 2026 शनिवार

सम्पादकीय

एआई के खतरे

एआई के सूत्रधार रहे शोधकर्ता लगातार धारदार होती एआई को लेकर जो गंभीर चिंता जता रहे हैं, उसमें मानव सभ्यता के लिए आसन्न संकट की आहट सुनायी देती है। पहले भी दबी–खुली जुबान में एआई के संस्थापक सूत्रधार ऐसी चिंता गाहे–बगाहे जाहिर कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब एन्थ्रोपिक के रिसर्चर जैकब कॉक्सन के इस्तीफे और उनकी इस बात पर व्यक्त की गई गंभीर चिंताओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो एन्थ्रोपिक व ओपन एआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में अहम भूमिका निभा चुका हो, यह दावा करता है कि एआई की बड़ी कंपनियां इंसानी जिंदगी के साथ जुआ खेल रही हैं, तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि एआई से जुड़े शोध–अनुसंधान के कार्य को क्या जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है? दरअसल, कॉक्सन की असली चिंता खुद को बेहतर बनाने वाली सुपरइंटेलिजेंस की तरफ बढ़ती अंधी होड़ है। जिसके बारे में आशंका जतायी जा रही है कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जो आगे चलकर कई क्षेत्रों में इंसानी क्षमताओं से भी आगे निकल सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,संसाधनों और संस्थानों को शिकार बनाने की क्षमता भी हासिल कर सकता है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि एन्थ्रोपिक के अपने अलाइनमेंट साइंस प्रमुख, इवान हुबिंगर ने भी माना है कि कंपनी के पास अभी तक सुपरइंटेलिजेंट सिस्टम को इंसानी हितों के अनुकूल बनाने का कोई समाधान मौजूद नहीं है। निश्चित रूप से ऐसी बातें एआई उद्योग के मूल में विद्यमान खतरनाक विरोधाभास को ही उजागर करती हैं। कंपनियां तेजी से यह मानकर चल रही हैं कि एडवांस्ड एआई से बहुत बड़े जोखिम मानवता के समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इस हकीकत को जानते–बूझते हुए भी इस क्षेत्र में जारी मारक स्पर्धा उन्हें ज्यादा सक्षम सिस्टम बनाने को बाध्य कर रही है।

दरअसल, एआई के क्षेत्र में जारी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा उन्हें लगातार उन्नत सिस्टम बनाने को मजबूर कर रही है। उनकी आशंका है कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरी कंपनी ऐसी पहल करके विश्व के एआई बाजार पर वर्चस्व बना लेगी। निश्चित रूप से यह अंधी होड़ एक दिन मानवता को एक भयावह तबाही के दरवाजे पर खड़ा कर सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज दुनिया में एआई के प्रयोग से चिकित्सा, विज्ञान और उत्पादन के क्षेत्र में आशातीत लाभ मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद तकनीकी प्रगति को सिर्फ इस आधार पर नहीं मापा जा सकता है कि उससे क्षमताएं कितनी बेहतर स्थिति में आ पहुंची हैं। एआई के क्षेत्र में की जा रही तरक्की के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही सुरक्षा और जवाबदेही भी उसी रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए। सही मायने में लगातार शोध–अनुसंधान के जरिये बड़े पैमाने पर उन्नत एआई क्षमताएं हासिल करने के गंभीर आक्षेप चिंता की बात है। यदि अमेरिका और चीन के बीच जारी गला–काट स्पर्धा शक्तिशाली एआई के विस्तार को तेज कर रही है और वहीं दूसरी ओर कंपनियां अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिये संघर्ष कर रही हैं तो इसके जोखिम कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक बढ़ जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में सरकारें इंसानियत के भविष्य से जुड़े फैसले टेक कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ सकती हैं। बड़ी एआई लैब्स के लिये लागू करने योग्य सुरक्षा मानक, स्वतंत्र निगरानी व जोखिम का पारदर्शी आकलन करना जरूरी है। इसके अलावा एआई की सबसे खतरनाक क्षमताओं के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमाएं तय करनी बेहद जरूरी हैं। एआई के खिलाफ दुनिया में उठ रही आवाजों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। निश्चित रूप से जब मानवता सभ्यता पर संकट हो और बात उसके भविष्य की हो, तो कोई भी लापरवाही भरा कदम घातक साबित हो सकता है।

नशे की गिरफ्त में युवा

उस व्यक्ति की त्रासदी का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है, जिसका बेटा नशे का आदी हो चुका है। इसी वजह से उसकी पढ़ाई छूट चुकी है और अब वह दिन भर कंप्यूटर गेम खेलता रहता है या दिन भर ट्रक के अड्डे पर जुआ खेलता रहता है। पिता इसलिए परेशान हैं कि वह अब उसके मादक पदार्थों पर भी हाथ साफ करने लगा है और उसे अपने बेटे के भविष्य का अनुमान है और अब वह इसी को लेकर फिक्रमंद है। हालांकि खुद पचास का पिता भी नशे के जाल में इस कदर फंसा हुआ है, उसके हाथ कांपने लगे हैं और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है।

बीते कुछ महीने के भीतर ऐसे मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। जिनका नशे की लत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वैसे लोग अब परामर्श और आपात हस्तक्षेप तक के लिए मनोचिकित्सकों या काउंसलरों के पास पहुंचने लगे हैं। संकट की भयावहता के चलते केंद्र सरकार अब नशा मुक्त भारत अभियान की बात कर रही है और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नशाखोरी के विरुद्ध बड़ी–बड़ी रैलियां कर रहे हैं।

युवाओं को शपथ दिलवाया जा रहा है, स्कूल–कालेजों को नशे के विरुद्ध माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त–दुरुस्त किया जा रहा है तथा बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मगर इसी बीच यह खबर भी आती है कि पंजाब में एक ग्रामीण ने जब मादक पदार्थों की धड़ल्ले से आपूर्ति पर सवाल उठाया, तो उसे प्रताड़ित किया गया और आखिर उसने आत्महत्या कर ली।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एम्स के 'नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर' के सहयोग से जारी की गई आधिकारिक रिपोर्ट 'मैग्नीट्यूड आफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया' के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि मादक पदार्थों की खरीद–बिक्री और नशे की समस्या अब केवल कुछ महानगरों या सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही। यह एक सर्वव्यापी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल और सामाजिक संकट का रूप ले चुकी है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 10 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के बीच लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनमें से 5.7 करोड़ से अधिक लोगों को तत्काल चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता है। वहीं, लगभग 3.1 करोड़ लोग भांग, गांजा या चरस जैसे कैनबिस उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति ओपियोइड्स (अफीम, हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स) के मामले में है। भारत में ओपियोइड का उपयोग वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना अधिक है। देश में करीब 2.26 करोड़ ओपियोइड उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से साठ लाख से अधिक लोग इस लत के गंभीर दुश्चक्र में फंस चुके हैं। जब तक समाज के भीतर से नशीले पदार्थों की मांग समाप्त नहीं होगी, यह जंग अधूरी रहेगी। हमें 'जेल नहीं, इलाज' और 'सहानुभूति, न कि तिरस्कार' के सिद्धांत को अपनाना होगा।

डालर का दबदबा और ब्रिक्स सम्मेलन से जगी उम्मीदें

—पुष्परंजन—

दुनिया भर के शेयर बाजार के खिलाड़ियों से लेकर ताकतवर केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों तक, सबकी नजरें ब्रिक्स की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की बैठक में होने वाले फैसलों पर टिकी हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन–देन में अमेरिकी डॉलर के दबदबे के लिए खतरा माना जाता है।

शाओमी के बिजनेस मॉडल को लेकर चीनी सत्ता के गलियारों में घबराहट ऐसे समय हो रही है, जब शनिवार से दिल्ली में ब्रिक्स शिखर बैठक होने जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने गुरुवार को कहा कि चीन को उम्मीद है कि भारत वहां निवेश करने और काम करने वाली सभी देशों की कंपनियों के लिए एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, पारदर्शी और बिना भेदभाव वाला बिजनेस माहौल देगा। गुओ ने साथ में इसकी भी घोषणा की कि राष्ट्रपति शी ब्रिक्स बैठक में नई दिल्ली जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ से उन रिपोर्टों के बारे में पूछा गया था, जिनमें कहा गया था कि भारत के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने शाओमी की जांच की सिफारिश की है। गुओ ने कहा कि उन्हें खास स्थिति के बारे में पता नहीं है।

भारत के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी के बिजनेस मॉडल और विदेशी निवेश नियमों के कथित उल्लंघन की एक विस्तृत जांच की सिफारिश की है। एसएफआईओ यह जांच करना चाहता है कि क्या 2020 की सीमा झड़पों के बाद चीनी निवेश पर कड़े नियमों के बावजूद शाओमी ने अनिवार्य मंजूरियां ली थीं या नहीं। कंपनी पर धन के प्रवाह और रॉयल्टी भुगतान जैसे मामलों में गड़बड़ी का संदेह है। यह प्रस्ताव अभी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की मंजूरी के लिए लंबित है। कोई सात साल बाद चीनी राष्ट्रपति शी भारत आ रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समिट में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ था, जो गुरुवार को क्लियर हो गया। चीन के लिए यह समिट इसलिए अहम है, क्योंकि यह ब्रिक्स की 20वीं सालगिरह है और यह ऐसे समय में हो रही है, जब वैश्विक शासन में अव्यवस्था बढ़ रही है।

जैसे–जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नजदीक आ रहा है, दुनिया भर के शेयर बाजार के खिलाड़ियों से लेकर ताकतवर केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों तक, सबकी नजरें इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की बैठक में होने वाले फैसलों पर टिकी हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन–देन में अमेरिकी डॉलर के दबदबे के लिए खतरा माना जाता है।

धीमी प्रगति के बावजूद, डी–डॉलरलाइजेशन (डॉलर पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया) चर्चा का विषय बन गई है। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वे बयान हैं, जिनमें उन्होंने ब्रिक्स देशों के समूह को चेतावनी दी थी कि अगर वे वैश्विक व्यापार में डॉलर के दबदबे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है।

मॉस्को, नई दिल्ली या पेइचिंग में बाजार संभालने वाले सभी मंत्रियों और अधिकारियों ने बार–बार जोर देकर कहा है कि ब्रिक्स का कोई भी देश डॉलर के खिलाफ किसी तरह की वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ रहा है। लेकिन, यह हाथी के दांत दिखाने जैसा है। डॉलर के एकाधिकार को समाप्त करने की छटपटाहट तो है। यदि ब्रिक्स के देशों में आपसी मतभेद न हों, तो डॉलर का विकल्प कब का तैयार हो जाता।

भले ही ब्रिक्स शिखर बैठक में डी–डॉलरलाइजेशन पर खुलकर चर्चा न हो, लेकिन सम्मेलन के दौरान देशों के बीच होने वाली बातचीत में करेंसी स्वैप (मुद्रा की अदला–बदली) और व्यापार ढांचे पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। मूल सदस्य देशोंकृभारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकाकृके नेताओं के बीच और हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए कई अन्य देशों, जैसे ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई और इथियोपिया, के नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत होने की उम्मीद है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार का मूल्य 1.17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था। माना जाता है कि यह सालाना औसतन 13 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। दुनिया के कुल निर्यात में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है। मगर, राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान निपटाने की दिशा में ब्रिक्स देशों के विभिन्न कदम, जैसे भारत और रूस के बीच रुपया–रूबल समझौता या डॉलर के बजाय युआन में व्यापार करने की चीन की कोशिशें, जितनी कारगर होनी चाहिए थीं, हुई नहीं।

साल 2000 में, सभी देशों के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा डॉलर के रूप में रखा जाता था। 2026 तक यह घटकर लगभग 57 फीसदी रह गया है। अर्थात, 'टाइगर अभी जिंदा है' की तर्ज पर डॉलर अभी जिंदा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बनाने वाली टीम के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'यह साफ तौर पर दिखाता है कि कई देशों के केंद्रीय बैंकर डॉलर का भारी भंडार रखने से जुड़े भू–राजनीतिक जोखिमों को बांटने के लिए या तो दूसरी मुद्राएं या फिर सबसे सुरक्षित निवेश, यानी बुलियन (सोना), खरीद रहे हैं।'

डॉलर पर भरोसे की कमी का यह असर अब खुद अमेरिका के केंद्रीय बैंक द्वारा सोना रखने के मामले में भी दिखने लगा है। सोना महंगा होने की मूल वजह अब सरकारें बन चुकी हैं। डच केंद्रीय बैंक ने इस साल मार्च और अगस्त के बीच उत्तरी अमेरिका से लंदन में लगभग 86 टन सोना ट्रांसफर किया, जिसकी कीमत 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा थी। इससे पहले, जनवरी 2026 में फ्रांस ने अमेरिका में रखा अपना 129 टन सोना बेच दिया था, जो उसके कुल भंडार का लगभग 5 प्रतिशत था। बिक्री से मिले पैसे से फ्रांस ने यूरोप में सोना खरीदा और उसे अपने केंद्रीय बैंक के वॉल्ट में जमा कर दिया। यह कदम लगभग 9 साल पहले राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जर्मनी के बुंडेसबैंक द्वारा उठाए गए उपाय जैसा ही है, जब उसने फ्रैंकफर्ट में अपने वॉल्ट में 300 टन सोना ट्रांसफर किया था।

मंगलवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, 'हालांकि ब्रिक्स किसी भी 'डी–डॉलरलाइजेशन नीति' के पक्ष में नहीं है, लेकिन सदस्य देश, जिनमें से कई प्रतिबंधों के कारण डॉलर में लेन–देन नहीं कर सकते, हम बस वही कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बेहतर है। अमेरिकी कदमों ने ही डॉलर पर भरोसे को कम किया है।'

भारत के नजरिए से यह समस्या काफी पेचीदा है, क्योंकि नई दिल्ली एक तरफ तो रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक बन गई है और दूसरी तरफ पश्चिमी बाजारों, टेक्नोलॉजी और पूंजी तक अपनी पहुंच भी बनाए रखना चाहती है। यहीं पर ब्रिक्स और भी अहम हो जाता है। अध्यक्ष देश की हैसियत से भारत किस करवट बैठता है, इस पर राष्ट्रपति ट्रंप नजरें गड़ाए बैठे हैं।

—लेखक जियोपॉलिटिकल मामलों के पत्रकार हैं।

संविधान की मूल भावना शब्दों में नहीं, उसके मूल्यों में है

—अखिल कुमार यादव—

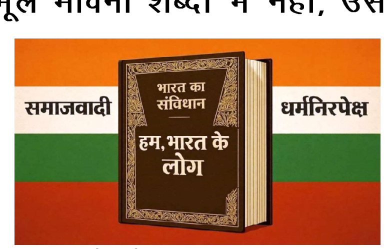

संविधान की प्रस्तावना में लिखे दो शब्द 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में इन शब्दों को लेकर सवाल उठाया और इन्हें संविधान की प्रस्तावना से हटाए जाने की बात कही। उनका तर्क है कि जब संविधान 26 नवंबर, 1949 को स्वीकार किया गया था, तब प्रस्तावना में न तो 'समाजवादी' शब्द था और न 'पंथनिरपेक्ष' दोनों शब्द बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए। इसलिए इन शब्दों को हटाकर संविधान को उसके मूल स्वरूप में वापस लाया जाना चाहिए। राजा भैया के तर्क का पहला हिस्सा ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही है। लेकिन समस्या वहां पैदा होती है, जहां इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है कि इन शब्दों को हटाना ही संविधान की मूल भावना की वापसी है। इतिहास और संविधान दोनों को समझने के लिए यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है कि किसी शब्द का संविधान में बाद में जुड़ना और उस शब्द में निहित संवैधानिक विचार का भी बाद में पैदा होना, दो अलग–अलग बातें हैं।

मूल संविधान की प्रस्तावना में भारत को 'सम्पूर्ण प्रभुत्व–संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' कहा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से इसमें 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए और भारत को 'सम्पूर्ण प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' कहा गया। यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ और देश उस समय आपातकाल के दौर से गुजर रहा था। इसलिए इन शब्दों को लेकर राजनीतिक विवाद होना स्वाभाविक है। लेकिन संवैधानिक प्रश्न का उत्तर केवल उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों से नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले 'पंथनिरपेक्ष' शब्द को समझना होगा। यह तर्क देना कि 1976 से पहले भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था, संविधान के मूल प्रावधानों को नजरअंदाज करना होगा। संविधान लागू होने के समय ही नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार या पोषण के लिए कर लगाए जाने से सुरक्षा देता है और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित सीमाएं तय करता है। जब ये सारे प्रावधान संविधान में शुरुआत से मौजूद थे, तब यह कहना कठिन होगा कि धर्मनिरपेक्षता की भावना 1976 में पैदा हुई। सच यह है कि 1976 में इस संवैधानिक भावना को प्रस्तावना में एक स्पष्ट नाम मिला।

'समाजवादी' शब्द का मामला भी कुछ ऐसा ही है। मूल प्रस्तावना में ही 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय' की बात कही गई थी। संविधान के नीति–निर्देशक तत्वों में राज्य को ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने की दिशा दी गई, जिसमें संसाधनों और अवसरों का अधिक न्यायपूर्ण वितरण हो। कमजोर वर्गों की सुरक्षा, समान अवसर और आर्थिक असमानताओं को कम करने की भावना संविधान की मूल संरचना में पहले से दिखाई देती है। इसलिए यह कहना तो तथ्यात्मक रूप से सही है कि 'समाजवादी' शब्द 1976 में जोड़ा गया, लेकिन यह कहना कि संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की सोच भी उसी वर्ष आई, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।

यहां एक और सवाल उठता है। यदि संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हर शब्द को केवल इसलिए हटाने की मांग की जाए कि वह 1949 की मूल प्रति में नहीं था, तो फिर संविधान के संशोधन की पूरी व्यवस्था का क्या अर्थ रह जाएगा? संविधान कोई पत्थर पर लिखी हुई ऐसी इबारत नहीं है जिसे उसके निर्माण के बाद कभी बदला ही न जा सके। संविधान निर्माताओं ने स्वयं अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान संशोधन की व्यवस्था की थी। इसका अर्थ है कि बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन संभव है। हां, यह शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का 2024 का फैसला इस बहस को और महत्वपूर्ण बना देता है। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत के सामने यही प्रमुख तर्क था कि ये शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे और 1976 में जोड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर इन्हें असंवैधानिक घोषित करने से इनकार किया। इस फैसले के बाद यह कहना कि इन शब्दों को हटाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, न्यायिक स्थिति के अनुरूप नहीं होगा। राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति इन शब्दों से असहमति रख सकता है, इनके अर्थ की आलोचना कर सकता है या इनके इस्तेमाल पर बहस की मांग कर सकता है, लेकिन संवैधानिक स्थिति यह है कि ये दोनों शब्द आज संविधान की प्रस्तावना का विधिवत हिस्सा हैं। एक महत्वपूर्ण भ्रम 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को लेकर भी है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म–विरोधी होना नहीं है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था किसी नागरिक को धर्म मानने से रोकती नहीं, बल्कि उसे अपनी आस्था चुनने की स्वतंत्रता देती है। राज्य का दायित्व नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव न करना है। इसलिए 'पंथनिरपेक्ष' शब्द को हटाने की मांग को सीधे धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक परंपराओं के विरोध के रूप में प्रस्तुत करना भी सही नहीं होगा। इसी तरह 'समाजवादी' शब्द का अर्थ भारत को किसी एक कठोर आर्थिक मॉडल में बांध देना भी नहीं है। भारतीय संविधान निजी संपत्ति, बाजार और लोकतांत्रिक आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करने की व्यवस्था नहीं करता। भारतीय संदर्भ में समाजवाद का संवैधानिक अर्थ सामाजिक और आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा अत्यधिक आर्थिक असमानताओं को कम करने की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता से जुड़ा है। इसलिए राजा भैया की बात पर स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस का आधार अधूरा इतिहास नहीं होना चाहिए। यह कहना सही है कि ये दोनों शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। यह भी सही है कि इन्हें 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। लेकिन इससे यह निष्कर्ष अपने आप नहीं निकलता कि इनके पीछे के संवैधानिक मूल्य भी 1976 में आयात किए गए थे।

दरअसल संविधान की मूल भावना को केवल 26 नवंबर, 1949 को लिखी गई प्रस्तावना के शब्दों में तलाशना संविधान को बहुत सीमित अर्थ में देखना होगा। संविधान की आत्मा उसके मौलिक अधिकारों में है, नागरिकों की स्वतंत्रता में है, समानता के अधिकार में है, धार्मिक स्वतंत्रता में है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्रतिबद्धता में है और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है जिसमें सत्ता जनता से आती है। राजनीतिक दलों और नेताओं को निश्चित रूप से संविधान की व्याख्या पर सवाल उठाने, संशोधन की मांग करने और जनता के सामने अपना विचार रखने का अधिकार है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जनता के सामने इतिहास को पूरा रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर यह बताया जाए कि 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द 1976 में जोड़े गए, तो साथ ही यह भी बताना चाहिए कि समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक–आर्थिक न्याय के अनेक संवैधानिक प्रावधान 1950 में संविधान लागू होने के समय से ही मौजूद थे। इसलिए असली बहस यह नहीं होनी चाहिए कि कोई शब्द 1949 में था या 1976 में आया। असली सवाल यह होना चाहिए कि क्या भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा देने की गारंटी को प्रभावी ढंग से निभा रहा है?

क्योंकि संविधान की शक्ति केवल उसके शब्दों में नहीं होती। शब्द दिशा बताते हैं, लेकिन संविधान की वास्तविक आत्मा तब दिखाई देती है जब सत्ता कमजोर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को समान नागरिक मानती है, व्यक्ति की आस्था को उसका निजी अधिकार समझती है और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को कम करने के लिए राज्य को जिम्मेदार बनाती है। 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की बहस इसलिए केवल दो शब्दों की बहस नहीं है। यह उस भारत की परिकल्पना पर बहस है जिसे संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र के आधार पर गढ़ने का प्रयास किया। इसलिए इतिहास का आधा सच लेकर संविधान की मूल भावना का फैसला करना उचित नहीं होगा। संविधान की मूल भावना 1949 के शब्दों में भी है, 1976 के संशोधनों में भी है और सबसे बढ़कर उन लोकतांत्रिक मूल्यों में है, जिन्हें संविधान प्रत्येक नागरिक के लिए सुनिश्चित करता है।

हिन्दी हमारी आवाज, हमारा आत्म सम्मान

—शम्भू शरण सत्यार्थी—

भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती। वह मनुष्य की स्मृतियों, संवेदनाओं, अनुभवों और सपनों को अपने भीतर सँजोकर रखती है। हम जिस भाषा में पहली बार माँ को पुकारते हैं, जिस भाषा में बचपन की कहानियाँ सुनते हैं, जिस भाषा में दुख में किसी का कंधा खोजते हैं और खुशी में किसी को आवाज देते हैं, वह भाषा हमारे जीवन का हिस्सा भर नहीं रहती, वह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। हिंदी भी हमारे लिए ऐसी ही भाषा है। वह करोड़ों लोगों की बोलचाल, संवेदना, साहित्य, पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन की भाषा है। इसलिए हिंदी दिवस केवल एक भाषा के सम्मान का अवसर नहीं बल्कि यह सोचने का दिन भी है कि हम अपनी भाषा के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हिंदी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उसका बोलने वाला कितने लोग हैं। असली सवाल यह है कि ज्ञान, शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, न्याय, विज्ञान और तकनीक की दुनिया में हिंदी को कितना सम्मान और अवसर मिला है।

हमारे समाज में अंग्रेजी का ज्ञान अक्सर योग्यता और प्रतिष्ठा का पर्याय मान लिया जाता है। अंग्रेजी जानना बुरा नहीं है। दूसरी भाषाएँ सीखना हमेशा मनुष्य की क्षमता को बढ़ाता है। समस्या तब पैदा होती है जब भाषा को बुद्धिमत्ता का प्रमाणपत्र बना दिया जाता है। किसी व्यक्ति की प्रतिभा, संवेदना, वैज्ञानिक दृष्टि या रचनात्मकता का मूल्य केवल इस आधार पर तय नहीं किया जा सकता कि वह अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, बुद्धिमत्ता का पैमाना नहीं। दुर्भाग्य यह है कि आज भी अनेक परिवारों में बच्चे से हिंदी बोलने पर कोई विशेष गर्व नहीं किया जाता लेकिन अंग्रेजी के कुछ वाक्य बोल लेने पर उसे आधुनिक और योग्य समझ लिया जाता है। विद्यालयों में भी कई बार भाषा ज्ञान का माध्यम बनने के बजाय सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को होता है जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम की सुविधा नहीं। भाषा उनके सामने अवसर का दरवाजा खोलने के बजाय दीवार बन जाती है।

हिंदी की शक्ति केवल उसके मानक रूप में नहीं, बल्कि उन तमाम लोकभाषाओं और बोलियों में भी है जिनसे उसका संसार समृद्ध हुआ है। भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, राजस्थानी और अनेक अन्य भाषिक रूप हिंदी क्षेत्र की सांस्कृतिक जमीन को सींचते हैं। इनके लोकगीतों, कहावतों, कथाओं और जीवन–अनुभवों ने हिंदी को व्यापक संवेदना दी है। इसलिए हिंदी को मजबूत करने का अर्थ इन भाषाओं को कमजोर करना नहीं हो सकता। हिंदी तभी समृद्ध होगी जब वह भारतीय भाषाओं के बीच पुल बनेगी, दीवार नहीं। हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती ज्ञान की भाषा को लेकर है। यदि विज्ञान की पुस्तकें, चिकित्सा संबंधी जानकारी, कानून की भाषा, तकनीकी शिक्षा, शोध सामग्री और आधुनिक ज्ञान का बड़ा हिस्सा किसी व्यक्ति की पहुँच से केवल भाषा के कारण दूर हो जाए, तो यह केवल भाषाई समस्या नहीं रहती, यह सामाजिक न्याय का प्रश्न बन जाती है। ज्ञान पर किसी एक भाषा का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। भारत जैसे बहुभाषी देश में ज्ञान जितनी अधिक भारतीय भाषाओं में पहुँचेगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा।

हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने की बात भी इसी संदर्भ में समझनी होगी। यह जरूरी नहीं कि हर नौकरी में हिंदी ही पर्याप्त हो। जहाँ अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की वास्तविक आवश्यकता है, वहाँ उसका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जहाँ किसी काम को हिंदी में बेहतर ढंग से किया जा सकता है, वहाँ केवल अंग्रेजी के आकर्षण के कारण हिंदी को पीछे रखना उचित नहीं।

विनोद साहनी हत्याकांडः मंत्री संजय निषाद की अगुवाई में निकला जुलूस, हत्यारों को फांसी देने की मांग

संवाददाता—गोण्डा। विनोद साहनी हत्याकांड के मामले में गोंडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अफसरों पर भड़क उठे। मंत्री ने पूछा कि इतनी फोर्स क्यों लगवा दिए। साथ ही कई अन्य मामले में नाराजगी जताई। इस दौरान निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे। मंत्री संजय निषाद ने बंद कमरे में डीएम व एसपी के साथ मंत्री बैठक कर चर्चा की। वहीं, कुछ देर बाद हत्याकांड को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मंत्री संजय निषाद की अगुवाई में सर्किट हाउस से जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता 'विनोद के हत्यारों को फांसी दो' के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांग रखी।

उधर, हत्याकांड के विरोध में शुक्रवार को ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण हत्यारों को फांसी देने और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पहले गांव में धरना दिया। इसके बाद शव लेकर मुख्य मार्ग की ओर बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। ग्रामीण वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में शव लेकर शाहपुर बाजार पहुंचे और सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री एवं सपा नेता योगेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता त्रिलोकी नाथ तिवारी और सपा प्रदेश सचिव दिग्विजय सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है। इसके पहले, गोंडा बॉर्डर से कुछ दूरी पर स्थित करनैलगंज चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। एडिशनल एसपी, सीओ समेत कई थानों की पुलिस को लगाया गया है। चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई। इसके अलावा गोंडा सर्किट हाउस, कलेक्ट्रेट और पुलिस कार्यालय के आसपास भी भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई। निषाद समाज समेत विभिन्न समाजों के नेताओं के गोंडा पहुंचने की सूचना को देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया की गतिविधियों की भी निगरानी की जा रही है।

उधर, मृतक विनोद साहनी के घर पर शुक्रवार सुबह सात बजे से ही बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। परसपुर, तरबगंज, नवाबगंज समेत कई थानों की पुलिस फोर्स को गांव में तैनात किया गया है। करनैलगंज से मृतक के घर जाने वाले रास्तों पर जगह—जगह पुलिस बल तैनात करने के साथ बैरिकेडिंग की गई है। पूर्व मंत्री एवं करनैलगंज के पूर्व विधायक योगेश प्रताप सिंह भी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ मौके पर मौजूद हैं। परिजनों का रो—रोकर बुरा हाल है। परिवार के कई सदस्य बार—बार रोते—रोते बेहोश हो जा रहे हैं। योगेश प्रताप सिंह और जिला प्रशासन के अधिकारी परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है।

सीमा से सटे नेपाल में 95 लाख के मोबाइल का सामान बरामद

संवाददाता—महराजगंज। भारत से कस्टम चोरी कर नेपाल ले जाए जा रहे मोबाइल से जुड़े सामानों की बड़ी खेप सीमा सटे नेपाल में पकड़ी गई है। नवलपरासी पुलिस और सशस्त्र प्रहरी की संयुक्त टीम ने 94 लाख 84 हजार नेपाली रुपये कीमती सामानों को बरामद किया है। तस्करी में प्रयुक्त पिकअप को भी कब्जे में लिया गया है।

जिला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी के सूचना अधिकारी डीएसपी मदन थापा ने बताया कि इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुर और सशस्त्र प्रहरी बल भूजहवा बीओपी की संयुक्त टीम सीमा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान भुजहवा क्षेत्र में एक पिकअप संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखते ही वाहन चालक पिकअप को लॉक कर मौके से फरार हो गया। तलाशी लेने पर पिकअप में बड़ी मात्रा में मोबाइल संबंधी सामान लदा मिला। बरामद सामान में 22 लाख 94 हजार रुपये मूल्य के 2,294 पीस मोबाइल एयरपॉड, 70 लाख 95 हजार रुपये के 44 हजार 300 पीस टेम्पर्ड ग्लास, 93 हजार रुपये के 930 पीस मोबाइल कवर और दो हजार रुपये मूल्य की एक बोरी प्लास्टिक शामिल है।

पुलिस के मुताबिक बरामद सामान और 20 लाख रुपये मूल्य के पिकअप वाहन को मिलाकर कुल कीमत 1 करोड़ 14 लाख 84 हजार रुपये आंकी गई है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए बरामद सामान और वाहन को महेशपुर भंसार कार्यालय भेज दिया गया है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इतनी बड़ी खेप भारत से किस रास्ते और किसके कहने पर नेपाल लाई जा रही थी?

अंबेडकर पार्क की भूमि पर कब्जा की जांच के आदेश

संवाददाता—देवरिया। क्षेत्र के सिरजमदेई गांव में अंबेडकर पार्क के लिए सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा की ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की। ग्रामीणों ने भूमि को कब्जामुक्त कराने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। गौरीबाजार थाना क्षेत्र के सिरजमदेई गांव निवासी बृजेश सिंह ने ग्रामीणों के हस्ताक्षर का शिकायती पत्र डीएम को दिया। बताया गया है कि गांव के गाटा संख्या 471 की 0.032 हेक्टेयर भूमि खतौनी में नवीन परती के नाम से दर्ज थी। तत्कालीन परगनाधिकारी देवरिया के 15 अगस्त 1980 के आदेश से भूमि अंबेडकर पार्क के लिए सुरक्षित की गई थी।

वर्ष 1387 से 1392 फसली में भी इसका उल्लेख दर्ज है। आरोप है कि इसके बावजूद भूमि प्रबंधक समिति ने नौ नवंबर 1981 को भूमि का आवासीय पट्टा गांव के कुछ अपात्र लोगों के नाम कर दिया। भूमि पर किसी ने भवन का निर्माण नहीं कराया और जमीन खाली पड़ी रही। आरोप है कि अब गांव का एक व्यक्ति अंबेडकर पार्क की भूमि पर खर—पतवार रखकर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। मामले की शिकायत तहसील दिवस और जनता दर्शन में भी की जा चुकी है। लेखपाल और तहसीलदार ने 20 अगस्त को अपनी आख्या रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी थी। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने डीएम से भूमि को कब्जामुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

क्षेत्रीय मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर डा. बंधु प्रसाद चौहान का जोरदार स्वागत

—भारतीय बस्ती संवाददाता— पौली (संतकबीरनगर)। भाजपा संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद शुक्रवार को डा. बंधु प्रसाद चौहान के प्रथम आगमन पर ब्लॉक प्रमुख राममिलन यादव के नेतृत्व में पौली क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने जगह—जगह फूल—मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।

पौली में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कहा कि डा. बंधु प्रसाद चौहान को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने से क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने के साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में तेजी आएगी।

स्वागत से अभिभूत डा. बंधु प्रसाद चौहान ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन किया जाएगा। संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के सम्मान को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को जन—जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए जमकर नारेबाजी की। समर्थकों में नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साह साफ नजर आया। कार्यक्रम में संघ जिलाध्यक्ष राममिलन यादव, जगदंबा लाल श्रीवास्तव, गणेश पांडेय, साधु यादव, कपिल देव कनौजिया, प्रिंस अगम सिंह, नित्यानंद, उमेश सिंह, लाल साहब, प्रदीप सिंह, रत्नेश पांडेय, कुलदीप पिंटू यादव, ध्रुव यादव, वीरेंद्र यादव, कुलदीप चौहान, चंद्रशेखर यादव, रमेश यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे।

पूर्वाचार्य महंत जयराम दास की पुण्यतिथि पर संतों ने किया नमन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि दर्शन मार्ग स्थित प्रसिद्ध लवकुश मंदिर के पूर्वाचार्य महंत जयराम दास महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को संतों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। लवकुश मंदिर के वर्तमान महंत रामकेवल दास के संयोजन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में रामनगरी के संत—महंतों ने साकेतवासी महंत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व का स्मरण किया।महंत रामकेवल दास ने कहा कि उनके गुरुदेव भजनानंदी संत थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सहज था। इसी कारण रामनगरी के संत—महंत उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने अपने साधना स्थल के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किया। उनके बताए मार्ग और आदर्शों को आत्मसात करते हुए मंदिर के उत्तरोत्तर विकास के लिए वह संकल्पित हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर प्रातरूकाल साकेतवासी महंत जयराम दास की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद नवीन वस्त्र धारण कराकर आरती—पूजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संतों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के अंत में संत—महंतों और भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। अतिथियों का स्वागत उत्तराधिकारी महंत रामदास ने किया।इस अवसर पर हनुमानगढ़ी के शीर्ष महंत ज्ञानदास महाराज के उत्तराधिकारी एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत संजय दास, हनुमानगढ़ी के पुजारी हेमंत दास, रामकचेहरी के महंत शशिकांत दास, पत्थर मंदिर के महंत मनीष दास, महंत माधवदास रामायणी, महंत रामकुमार दास, महंत राजेश पहलवान, महंत वैदेही वल्लभ शरण, महंत राजीव लोचन शरण, प्रेममूर्ति कृष्णकांत दास, कृष्णकुमार जयपुरिया खलीलाबाद, महंत शिवराम दास, नागा रामलखन दास, पार्षद पुजारी रमेश दास, ओम दास, संतदास सहित बड़ी संख्या में संत—महंत उपस्थित रहे।

मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने भरी हुंकार

संवाददाता—महराजगंज। वभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की कार्यकर्त्रियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय परिसर में बैठक की। जिलाध्यक्ष छाया भारती के नेतृत्व में कार्यकर्त्रियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांगपत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। इसमें बढ़ाई गई 25सौ रुपये की प्रोत्साहन राशि को मूल मानदेय में शामिल करने, लंबित भुगतान कराने व जीपीएस आधारित उपस्थिति व्यवस्था समाप्त करने की मांग की। चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो संगठन आंदोलन व प्रदर्शन करने को बाध्य होगा।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मूल मानदेय में 15 सौ रुपये व प्रोत्साहन राशि में 25 सौ रुपये की बढ़ोतरी की है। 25 सौ रुपये को भी मूल मानदेय में शामिल किया जाए। इसका हर माह नियमित भुगतान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि पूर्व से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी कई जिलों में नियमित नहीं है। कई महीनों की राशि लंबित है। कहीं छह महीने तो कहीं सालभर बाद एक—दो महीने की राशि मिल रही है। इससे कार्यकत्रियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने पोषण ट्रैकर के माध्यम से लागू जीपीएस आधारित उपस्थिति व्यवस्था का भी विरोध किया। कहा कि गांवों में नेटवर्क की समस्या रहती है, आर्थिक परेशानी के कारण मोबाइल रिचार्ज कराना भी मुश्किल होता है। विभागीय बैठक, प्रशिक्षण व अन्य सरकारी कार्यों के लिए केंद्र से बाहर रहने पर जीपीएस उपस्थिति में भी दिक्कत आती है। इस दौरान सरोज जायसवाल, राजमती, सोना, आयशा, ज्ञानमती, शोभा, सदरुन, शीला, सीमा, संगीता, अनीता, सपना, सुमित्रा, जावित्री, शीशमली, पूनम, कमलावती, विंध्यवासिनी, सरोज, रीना आदि मौजूद रहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बढ़ाई गई प्रोत्साहन राशि को मूल मानदेय में शामिल करने, लंबित भुगतान कराने व जीपीएस आधारित उपस्थिति व्यवस्था समाप्त करने की मांग की।

संस्कृति भूलकर सत्ता के लिए अपना रहे हथकंडे, सपा—कांग्रेस पर ब्रजेश पाठक ने बोला हमला

संवाददाता—देवरिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल भारतीय संस्कृति को भूलकर किसी भी तरह सत्ता हासिल करने के लिए तरह—तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या पूर्वांचल का कोई जिला, गुंडे, बदमाश और माफिया खुलेआम सड़कों पर घूमते थे। प्रदेश में कानून—व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव आया है। सरकार का उद्देश्य विकास के साथ सुरक्षित और बेहतर उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को कसया रोड स्थित पलक लॉन में पूर्व अधिवक्ता स्व. राजेंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से भाजपा की सरकार चल रही है और साढ़े नौ वर्ष होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। प्रदेश की जनता ने भी भाजपा को लगातार

आशीर्वाद दिया है।

उन्होंने कहा कि 35 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार किसी सरकार के बनने की स्थिति बनी है। यह देवऋषियों और देवरहा बाबा की धरती है। यहां से उठने वाली आवाज पूरे देश में जाती है। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों से सज्जनता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना होगा कि राष्ट्रप्रेम, भारत माता और उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर बदलने वालों को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने विकास और प्रदेश की बेहतर छवि के लिए मिलकर कार्य करने की अपील की। इस मौके पर जनपद के प्रभारी मंत्री उदयशंकर सिंह ने स्व. राजेंद्र किशोर शाही के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आयोजक एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद शशांक मणि, विधायक दीपक मिश्र शाका, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, जिलाध्यक्ष काली प्रसाद, नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह, जिला पंचायत प्रशासक पं. गिरीश चंद्र तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

शिक्षामित्रों ने सीएम को भेजा ज्ञापन, 25 साल से शिक्षा व्यवस्था की रीढ़, अब सेवा सुरक्षा और मानदेय बढ़ाने की मांग

संवाददाता—श्रावस्ती। शिक्षामित्रों ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। शुक्रवार को 5:00 बजे शिक्षामित्र संगठन ने बताया कि यह ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के जरिए सौंपा गया, जिसमें जल्द से जल्द समस्याओं को सुलझाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में करीब 1.47 लाख शिक्षामित्र लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। संगठन ने कहा कि शिक्षामित्र पिछले 25 सालों से शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं। इसके बावजूद उनकी कई सेवा से जुड़ी समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई हैं। संगठन की मुख्य मांगों में नवंबर 2026 में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में शिक्षामित्रों को आवेदन करने का मौका देना शामिल है। इसके अलावा, शिक्षामित्रों की सेवा से जुड़ी समस्याओं के लिए सेवा नियमावली बनाने और उनकी सेवा अवधि 62 साल करने की मांग भी की गई है। संगठन ने जनपद और दूसरे जिलों में ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। ज्ञापन में सरकार का धन्यवाद भी किया गया, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18 हजार रुपये हर महीने कर दिया गया है। साथ ही, कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए भी आभार जताया गया। संगठन ने कहा कि शिक्षामित्रों की सालों पुरानी सेवाओं और उनके काम को देखते हुए, उनकी बाकी मांगों पर भी अच्छा फैसला लेना जरूरी है। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे शिक्षामित्रों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दें और जल्द से जल्द उनका समाधान कराएं, ताकि उन्हें नौकरी में स्थिरता और राहत मिल सके।

आत्महत्या निरोध दिवस पर छात्रों ने ली शपथ

संवाददाता—बलरामपुर। विश्व आत्महत्या निरोध दिवस पर एमएलके पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों के साथ ही रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में शिक्षक—शिक्षिकाओं और छात्र—छात्राओं को आत्महत्या निरोध एवं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रो. जेपी पाण्डेय ने किया। उन्होंने आत्महत्या की समस्या के प्रति सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता को जरूरी बताते हुए विद्यार्थियों से सकारात्मक सोच और जीवन—मूल्यों से जुड़ने की अपील की। विशिष्ट अतिथि गायत्री शक्तिपीठ के सतीश चंद्र मिश्र रहे। संचालन कृतिका तिवारी ने किया। मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. स्वदेश भट्ट ने कहा कि आत्महत्या की रोकथाम के लिए व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति समझना और उसकी बात संवेदनशीलता से सुनना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर समय से मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। डॉ. सुनील कुमार शुक्ला ने परिवार, संस्कृति और सामाजिक सहयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि परिवार और समुदाय के साथ संवाद मजबूत करना तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना रोकथाम में महत्वपूर्ण है। राजर्षि मणि त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को संवाद करें, सुनें, साथ दें, जीवन को चुनें का संदेश दिया। उन्होंने आसपास के लोगों की भावनात्मक परेशानियों के प्रति संवेदनशील रहने व जरूरतमंद को उचित सहायता लेने के लिए प्रेरित करने की अपील की।

कर्मचारियों की मांगों को लेकर बैंकों में हड़ताल, काम-काज प्रभावित

संवाददाता—देवरिया। पांच दिवसीय कार्य सप्ताह और पीएलआई में भेदभाव को लेकर शुक्रवार को जिले भर के बैंककर्मी हड़ताल पर रहे। इसके चलते बैंकों में कामकाज प्रभावित रहा। ग्राहकों को बैरंग हाथ वापस लौटना पड़ा। जगह—जगह बैंककर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर मांगें नहीं माने जाने पर सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर शुक्रवार को बैंककर्मियों ने कामकाज ठप कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक व पंजाब नेशनल बैंक समेत सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों पर ताले लटक गए। सुबह 11 बजे शहर के स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर कर्मचारी एकत्रित हुए। यहां से शहर में नारेबाजी करते हुए बैंककर्मी सुभाष चौक पर पहुंचे जहां सभा की। जिला मंत्री रैश्री प्रसाद ने कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंक यूनियंस के बीच मार्च 2024 में हुए हुए 12 वें द्विपक्षीय समझौते में शनिवार को अवकाश घोषित करने को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी सरकार के तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं जारी हुआ। काम का लगातार दबाव बढ़ने के चलते बैंक कर्मचारियों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए यह व्यवस्था जरूरी है। पीएलआई में भेदभाव खत्म होना चाहिए। प्रदर्शन में सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी शामिल रहे। इस दौरान अध्यक्ष कुलदीप शाह, संयुक्त मंत्री सौरभ दास, राकेश व हर्षवर्धन मौजूद थे।

कुशोत्पाटिनी अमावस्या पर जीवंत हुई अयोध्या की वैदिक परंपरा

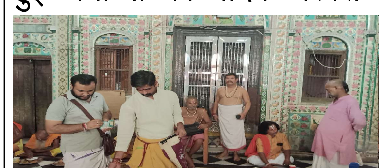

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या शुक्रवार को रामनगरी में श्रद्धा, आस्था और वैदिक परंपराओं के साथ कुशोत्पाटिनी अमावस्या के रूप में मनाई गई। गोपाल मंदिर में महंत विशंभर दास महाराज के संयोजन में आयोजित धार्मिक आयोजन में संत—महंतों, वैदिक आचार्यों और धर्माचार्यों ने विधि—विधान से कुश का पूजन—अर्चन किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कुश उखाड़कर अपने घर ले गए।सनातन परंपरा में कुश को अत्यंत पवित्र माना गया है। वर्षभर देवी—देवताओं और पितरों के पूजन, यज्ञ, जप, धार्मिक अनुष्ठान तथा विभिन्न मांगलिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन विधिपूर्वक उखाड़ी गई कुश का प्रयोग पूरे वर्ष धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। भाद्रपद अमावस्या पर स्नान, ध्यान और दान का भी विशेष महत्व माना गया है।

गोपाल मंदिर के आचार्य वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि वैदिक सनातन धर्म में कुशोत्पाटिनी अमावस्या का विशेष स्थान है। इस दिन स्नान—ध्यान के बाद दान—पुण्य करना चाहिए और विधिपूर्वक कुश उखाड़कर घर लानी चाहिए। इसी कुश का उपयोग वर्षभर यज्ञ, जप, पूजा—पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिन अन्नदान एवं प्रसाद वितरण की भी विशेष महत्ता है। जरूरतमंदों और श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है।इस अवसर पर महंत विशंभर दास महाराज ने संत—महंतों, वैदिक विद्वानों और आचार्यों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की। आयोजन में अयोध्या के सैकड़ों संत—महंत एवं वैदिक आचार्य शामिल हुए। महंत जी के सेवक विजेंद्र कुमार द्विवेदी ने आगंतुक संतों और अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया।कुशोत्पाटिनी अमावस्या के इस आयोजन में रामनगरी की सनातन परंपरा, वैदिक संस्कृति और संत परंपरा का अनुपम संगम दिखाई दिया।

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से 500 करोड़ का कारोबार प्रभावित

संवाददाता—बहराइच। पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल की। जिले के विभिन्न बैंकों में कर्मचारी कामकाज से विरत रहे। इससे बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं और करीब 500 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आवाह्न पर शुक्रवार को जिले के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। सभी बैंक संगठन के अधिकारी कर्मचारी इंडियन बैंक अंचल कार्यालय में प्रदर्शन किया। उधर सुबह बैंक खुलने की उम्मीद में पहुंचे ग्राहकों को हड़ताल की जानकारी मिलने पर मायूस होकर लौटना पड़ा। नकदी जमा करने, निकासी, चेक जमा करने समेत कई जरूरी बैंकिंग कार्य नहीं हो सके। इसका सबसे अधिक असर व्यापारियों और रोजाना बैंकिंग लेन—देन करने वाले लोगों पर पड़ा। कई कारोबारियों के भुगतान अटक गए, जबकि जरूरी लेन—देन के लिए लोगों को अगले कार्यदिवस का इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारियों ने कहा कि पांच दिन बैंकिंग की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई। कर्मचारियों ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार बैंक खुले रहें और शनिवार—रविवार अवकाश हो। पूर्व में द्विपक्षीय समझौते के बाद इस प्रस्ताव पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया। इस अवसर पर मंडल सचिव नागेन्द्र सिंह, जिला मंत्री, लालजी जायसवाल, अमित वर्मा, राहुल मांझी, बाबू लाल, रोहित श्रीवास्तव, अंकित अग्रवाल, ऋषभ, रविशंकर, तरुण शर्मा, रंजीत कुमार त्रिपाठी, प्रहलाद, रमन सिंह, यज्ञराम यादव, अभय जोशी, कमाल खान, जमील खान, शक्ति कुमार, पंकज गौड़, महेश कुमार, सतीश यादव आदि मौजूद रहे।

डीएम ने दिए अवैध स्कूल सील करने के निर्देश

संवाददाता—बलरामपुर। बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों पर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे राजकीय इंटर कॉलेज दारीचौरा के निरीक्षण के दौरान डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन ने जिला विद्यालय निरीक्षक को ऐसे स्कूलों की तत्काल पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने और जरूरत के मुताबिक उन्हें सील करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि छात्रों के भविष्य और उनकी पढ़ाई से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बिना मान्यता स्कूल चलाना नियमों का उल्लंघन है और इससे विद्यार्थियों की शिक्षा व भविष्य प्रभावित हो सकता है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने इंटर कॉलेज की विभिन्न कक्षाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्रों की उपस्थिति, पढ़ाई की व्यवस्था, उपलब्ध शिक्षण संसाधनों और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्रों के सीखने के परिणाम बेहतर करने और शिक्षण व्यवस्था में लगातार सुधार पर जोर दिया। डीएम ने छात्रों का नियमित मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए। कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनके लिए अतिरिक्त और सुधारात्मक कक्षाएं चलाने को कहा। डीएम ने विद्यालय का वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर भी देखा। उन्होंने तय पाठ्यक्रम और शैक्षिक गतिविधियों को निर्धारित समय में पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही छात्रों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और जरूरत के अनुसार शिक्षण व्यवस्था में सुधार करते रहने को कहा। विद्यार्थियों की संख्या और कक्षाओं की स्थिति की समीक्षा के बाद उन्होंने आवश्यकता के अनुसार सेक्शन बढ़ाने के निर्देश भी दिए, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके और कक्षाओं का संचालन प्रभावी ढंग से हो। डीएम ने विद्यालय में संचालित श्पंखश करियर गाइडेंस कक्ष का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न करियर विकल्पों की जानकारी नियमित रूप से दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समय रहते सही करियर मार्गदर्शन मिलने से विद्यार्थी अपने भविष्य की दिशा बेहतर तरीके से तय कर सकेंगे। विद्यालय परिसर और उपलब्ध भूमि का निरीक्षण करते हुए डीएम ने कहा कि इंटर कॉलेज में पर्याप्त जगह उपलब्ध है। उन्होंने उपलब्ध भूमि और संसाधनों का अधिकतम उपयोग शैक्षिक गतिविधियों के लिए करने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक समेत संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

मां के साथ आत्महत्या करने पहुंची बेटी, बुजुर्ग की गोद में रखी पेट्रोल की बोतल

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। जिले में पारिवारिक संपत्ति और मृतक आश्रित कोटे की नौकरी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। न्याय न मिलने और पारिवारिक कलह से हताश होकर एक महिला अधि ाकारियों के पास आत्मदाह करने पहुंच गई। पुलिस और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महिला द्वारा अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, यह पूरा विवाद मृतक आश्रित कोटे की नौकरी और पारिवारिक संपत्ति पर कब्जे को लेकर है। महिला के पिता की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर भाई को अनुकंपा (आश्रित कोटे) के आधार पर नौकरी मिली थी।

दुर्भाग्यवश भाई की भी मृत्यु हो गई। अब भाई के निधन के बाद मिलने वाली सरकारी धनराशि और आश्रित कोटे की अगली नौकरी को लेकर विवाद गहरा गया है। परिवार के अन्य सदस्यों की या तो मृत्यु हो चुकी है या वे लापता हैं। फिलहाल, यह महिला ही अपनी बुजुर्ग और बीमार मां की देखभाल कर रही है। शिकायतकर्ता महिला ने अपनी भाभी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि भाभी ने पुश्तैनी मकान पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है। भाभी ने अपनी बीमार सास (महिला की मां) और ननद को बेदखल कर घर से बाहर निकाल दिया है। महिला का कहना है कि जब भी वह अपनी मां को लेकर घर में रहने या अपना हक मांगने की कोशिश करती है, तो उसे धमकाकर वहां से भगा दिया जाता है।

घर से निकाले जाने और मां की बीमारी से टूट चुकी महिला ने जब आत्मदाह की चेतावनी दी, तो प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने महिला से उसका प्रार्थना पत्र लिया और उसे शांत करवाया। पुलिस और प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जाएगी। प्रशासन ने महिला को उसका कानूनी हक दिलाने और मकान पर कब्जा वापस दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी आश्वासन दिया है।

3000 बैंककर्मी हड़ताल पर, 500 करोड़ का लेनदेन प्रभावित

संवाददाता–गोरखपुर। बैंक प्रबंधन, वित्त मंत्रालय और यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बीच केंद्रीय श्रमायुक्त कार्यालय में दो दिनों से चल रही वार्ता विफल होने के बाद बैंक कर्मियों ने शुक्रवार को हड़ताल कर दी। करीब 3000 बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। जिससे 500 करोड़ से अधिक का लेनदेन प्रभावित हुआ है। बड़ी संख्या में बैंक कर्मियों ने एसबीआई मुख्य शाखा पर एकत्र होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।हड़ताल में जिले के स्टेट बैंक समेत सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के करीब 3000 अधि ाकारी–कर्मचारी शामिल हुए हैं। यूएफबीयू में एआइबीइए, एआइबीओसी, एनसीबीई, एआइबीओए, बीईएफआइ, आइएनबीओसी और आइएनबीईएफ समेत सात यूनियनें शामिल हैं। ये यूनियनें बैंकिंग कार्यबल के 90 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि यूएफबीयू की प्रमुख मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग, बैंक अधिकारियों के लिए प्रस्तावित पीएलआई की समान योजना, आइडीबीआई के विदेशीकरण पर रोक और पेंशन अपडेशन शामिल हैं। यूएफबीयू के संयोजक यूपीएन सिंह ने बताया कि 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की हड़ताल भी प्रस्तावित है। मांगें नहीं मानी गईं तो अक्टूबर के अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल का प्रस्ताव है।

किराये के कमरे में मिला सिपाही का शव

संवाददाता–अंबेडकरनगर। दो दिन के अवकाश के बाद ड्यूटी पर लौटे पुलिस लाइन में तैनात सिपाही का शव शुक्रवार सुबह किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मऊ जिले के कोपागंज के नौसेमर निवासी संदीप कुमार पुलिस लाइन में मेस मुंशी के पद पर तैनात थे। वह दो दिन के अवकाश पर घर गए थे। गुरुवार शाम वह वापस लौटकर पुलिस लाइन के निकट स्थित अपने किराए के कमरे में पहुंचे थे।

शुक्रवार सुबह करीब 5रू30 बजे कमरे में उनका शव फंदे से लटका मिला। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच–पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में सिपाही की मौत के पीछे पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। एएसपी डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। परिजनों को सूचना दी गई है।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–
वाद सं0– /2026
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय बांसी जिला सिद्धार्थनगर
राजू आदि
बनाम
वुधई आदि

1. बुधई पुत्र फागू साकिन उड़वलिया तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर 2. चन्द्रिका वालिग 3. राजेन्द्र वालिग 4. बबलू वालिग 5. गोर्रे वालिग 6. अजय वालिग 7. मनोज वालिग 8. शब्द वालिग पुत्रगण विन्देश्वरी साकिनान मौजा उड़वलिया तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर 9. सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर 10. ग्राम पंचायत उड़वलिया द्वारा ग्राम प्रधान निवासी ग्राम उड़वलिया तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 26–09–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 26 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जवाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 10 माह 09 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

– द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद संख्या 368 / 2025
निरंकारनाथ मिश्रा आदि
बनाम
विश्वकर्मानाथ आदि

1. विश्वकर्मानाथ पुत्र रामलखन 4. ओमकारनाथ पुत्र त्रिभुवन निवासीगण ग्राम मिश्रौलिया तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसीलइ व जिला बस्ती

तारीख पेशी 04–11–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 04 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

बेटे का जन्मदिन मनाने से पहले पिता की करंट से मौत

संवाददाता–गोरखपुर। चौरीचौरा थानाक्षेत्र के चकदेईया में शुक्रवार को डीजे का तार जोड़ते समय शहर के बशारतपुर निवासी शामुएल वरना वास उर्फ विक्की (35) पुत्र इमैनुअल वरना वास की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। आनन फानन में आसपास के लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया, जहां पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

अदालती नोटिस

अपील के सुनवाई के लिए नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(धारा 41 नियम 14 व्या0प्र0सं0)
न्यायालय–श्रीमान अपर जनपद न्यायाधीश बांसी सिद्धार्थ नगर
सिविल अपील सं0 95 / 2025
सतीशधर द्विवेदी आदि
बनाम
अरूणदेवधर द्विवेदी आदि

1. अरूणदेवधर द्विवेदी 2. वरूणदेवधर द्विवेदी 3. राजीवधर द्विवेदी पुत्रगण उमाशंकरधर द्विवेदी

–प्रत्युत्तरदातागण प्रथम पक्ष

5. यतीन्द्रधर द्विवेदी 6. नरेन्द्रधर द्विवेदी पुत्रगण गिरीशधर द्विवेदी 7. सूरजधर द्विवेदी 8. शरदधर द्विवेदी पुत्रगण योगीशधर द्विवेदी 9. मु0 साधना विधवा योगीशधर द्विवेदी 10. मु0 मीना देवी विधवा गिरीशधर द्विवेदी

–प्रत्युत्तरदातागण द्वितीय पक्ष

समस्त प्रत्युत्तरदातागण निवासी सा0 रमवापुर दूबे तप्पा असनार परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 29–09–2026

आपको सूचना दी जाती है कि मामले को आदेश डिक्री की अपील इस उपस्थित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गयी है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा दिनांक **29–09–2026** नियत की गयी है। यदि इस अपील में आप की ओर से आप स्वयं या आपके अधिवक्ता या आपके लिए कार्य करने के लिए विधिक प्राधिकृत कोई व्यक्ति उक्त नियत तिथि को समय 10:00 अपरान्ह उपसंजात नही होगा तो वह आपके अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जायेगी।

यह आज दिनांक **11–09–2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

द0 हाकिम

2027 में पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाएगी कांग्रेस –ओमप्रकाश महतो

संवाददाता–गोरखपुर। कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पिछड़े वर्ग को साधने की कवायद तेज कर दी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रभारी ओमप्रकाश महतो ने शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि,जितनी जिसकी संख्या, उतनी उसकी भागीदारी के सिद्धांत को जमीन पर उतारा जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग बढ़–चढ़कर हिस्सेदारी करेगा और संगठन में भी पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

ओमप्रकाश महतो ने संकेत दिया कि संगठन में काम करने वाले संघर्षशील, जुझारू और समर्पित नेताओं को चुनावी मैदान में उतरने का अवसर मिलेगा। कहा कि पिछड़े वर्ग को केवल चुनाव के समय याद करने के बजाय उसे संगठन और सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जय हिंद और प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव के नेतृत्व में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया।

बैठक में प्रदेश महासचिव एवं महाराजगंज–गोरखपुर प्रभारी देवेंद्र कुमार निषाद धनुष, एआईसीसी पूर्वांचल जोन के ऑब्जर्वर राधेश्याम जायसवाल, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशोक निषाद, शहर अध् यक्ष राजकुमार यादव, रमेश चंद्र जायसवाल, रामनयन, सतीश साहनी, बालकृष्ण निषाद, आनंद कुमार निषाद, रुद्रनाथ साहनी, डॉ. अखिलेश शर्मा समेत अन्य उपस्थित रहे।

स्कूल से निकलीं दो छात्राएं अयोध्या में मिलीं

संवाददाता–गोरखपुर। पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव से स्कूल जाने के बाद लापता हुई दो छात्राओं को पुलिस ने शुक्रवार सुबह अयोध्या से बरामद कर लिया। दोनों छात्राएं गुरुवार दोपहर स्कूल से घर नहीं लौटी थीं। उनकी साइकिल और स्कूल बैग सड़क किनारे मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की मदद से तलाश शुरू की तो उनका सुराग अयोध्या में मिला। पुलिस के अनुसार, गांव निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 10 सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे गांव की ही दूसरी छात्रा के साथ भटहट कस्बे स्थित एक इंटर कॉलेज में पढ़ने गई थी। दोपहर 1 बजे छुट्टी के बाद भी दोनों घर नहीं लौटीं। करीब ढाई बजे परिजनों को गांव की ओर जाने वाली पक्की सड़क से कुछ दूरी पर छात्राओं की साइकिल और स्कूल बैग पड़े मिले। इससे परिवार के लोग घबरा गए।बेलो चौकी प्रभारी अनीश कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की मदद से छात्राओं का सुराग अयोध्या में मिला।

कमरे में मिली इंजीनियर की लाश, चार दिन से बंद मकान से आई दुर्गंध, सोफा सेट पर मिला शव

संवाददाता–गोरखपुर। खोराबार थाना क्षेत्र के सहारा एस्टेट में शुक्रवार सुबह कमरे में इंजीनियर का शव मिला। मकान से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो सोफा सेट पर 45 वर्षीय अभिषेक त्रिपाठी का शव पड़ा मिला। शव करीब तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, सहारा स्टेट के मल्हार स्थित मकान नंबर 2/202 में अभिषेक त्रिपाठी रहते थे। वह मूल रूप से देवरिया जिले के रहने वाले थे। आसपास के लोगों के मुताबिक, पिछले करीब चार दिनों से मकान का दरवाजा बंद था। अभिषेक भी इस दौरान बाहर नहीं दिखाई दिए। शुक्रवार सुबह मकान से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर खोराबार पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर अंदर प्रवेश किया तो सोफा सेट पर अभिषेक का शव मिला। सूचना के बाद फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और कमरे की बारीकी से छानबीन कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने घटना की जानकारी अभिषेक के परिवार के लोगों को दे दी है। उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। कमरे में किसी तरह के संघर्ष या अन्य संदिग्ध स्थिति के संकेत हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। सीओ कैंट कीर्ति निधि आनंद ने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी।

लोकार्पण की तैयारियों के बीच सीएम ग्रिड सड़क में दिखने लगी खामियां

संवाददाता–गोरखपुर। करीब 45.14 करोड़ रुपये से राप्तीनगर वार्ड के शाहपुर इलाके में बन रही सीएम ग्रिड फेज–1 की स्मार्ट सड़कें लोकार्पण से पहले ही निर्माण की खामियों से घिर गई हैं। 14 सितंबर से पूर्व लोकार्पण की तैयारी के बीच नगर आयुक्त अजय जैन के निरीक्षण में उखड़े–खाबड़ टाइल, लेवल से बाहर चौंबर, डक्ट के बाहर बिजली के तार और फुटपाथ पर अतिक्रमण मिला। बिजली के पोल भी बैनर–पोस्टर और स्टीकर से अछूते नहीं थे। काम की धीमी रफ्तार और मौके पर मिली इन खामियों पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। नगर आयुक्त अजय जैन ने कार्यदायी संस्था मेसर्स शिवाश कंस्ट्रक्शन एण्ड ल्युमस इंफ्रा (जेवी)को श्रमशक्ति बढ़ाकर दो दिन में खामियां दूर करने और शेष काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। ताकि 14 सितंबर तक परियोजना को लोकार्पण के लिए तैयार किया जा सके। सीएम ग्रिड फेज–1 के तहत राप्तीनगर वार्ड के शाहपुर इलाके में लगभग 45.14 करोड़ रुपये की लागत से तीन प्रमुख सड़कों को आधुनिक स्मार्ट सड़क के रूप में विकसित की जा रही है। 6 नवंबर 2024 कार्यादेश हुआ, मई माह में काम पूरा होना था लेकिन 22 माह बाद भी काम अधूरा है। नगर आयुक्त ने निर्माण की गुणवत्ता और बचे हुए कार्यों की स्थिति देखी। इलेक्ट्रिकल पैनल अभी साइट पर स्थापित नहीं होने और केबल को भूमिगत करने का काम अधूरा मिलने पर इसे तत्काल पूरा कराने को कहा। पेवर ब्लॉक्स और एफआरपी चौंबर की फिनिशिंग का काम भी अधूरा मिला। उन्होंने पेवर ब्लॉक्स की फिनिशिंग पूरी कराने के साथ उखड़े–खाबड़ टाइलों को तत्काल दुरुस्त कराने, डक्ट के ऊपर–नीचे लगे चौंबरों को सही लेवल पर लगाने और बिजली के तारों को डक्ट के अंदर करने का निर्देश दिए।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
अदालत– श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
निगरानी सं0–95 / 2025
रामशंकर
बनाम
प्रभावती आदि

1. प्रभावती उम्र लगभग 60 वर्ष पत्नी नन्दलाल 2. नन्दलालद उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र स्व0 राम सुमेर चौधरी 3. राजेश कुमार उर्फ खन्ना चौधरी उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र स्व0 राम सुमेर चौधरी निवासीगण ग्राम बरसांव पोस्ट भेलखा विकास खण्ड बस्ती सदर तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती 4. जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी बस्ती 5. रिटर्निंग आफिसर विकास खण्ड–बस्ती सदर तहसील व जिला बस्ती (दिनांक 06.06.2021) को बस्ती सदर ब्लाक मे तैनात आर0ओ0 उप चुनाव मे 6. सरकार उत्तर प्रदेश

तारीख पेशी 22–09–2026

अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् ई0
रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 22 महीना 09 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत– श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मु0न0–681 / 1994
मुतफरिका सं0– 147 / 2025
रामधीरज
बनाम
पाटनदीन आदि

1/2 श्रीमती शिवकला पत्नी लोदर निवासी ग्राम रघुनाथपुर (मैनसर) पोस्ट रघुनाथपुर तहसील हर्रैया जिला बस्ती 1/3 शशिकला पत्नी शिवपूजन 1/4/1 गीता विधवा श्रीनेवास 1/4/2 अमित पुत्र श्रीनेवास 1/4/3 सुमित पुत्र श्रीनेवास 1/4/4 विन्दू पुत्री श्रीनेवास 1/4/5 इन्दू पुत्री श्रीनेवास 1/5 श्रीकान्त उर्फ रोहित पुत्र पाटनदीन 2. जगदीश पुत्र पाटनदीन निवासीगण पोखरनी तप्पा हवेली परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 30–10–2026

हरगाह मुद्दई मजकूरुसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबूदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 30 माह 10 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबूदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान प्रथम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
वाद संख्या 281 / 2021
राजेश कुमार सिंह
बनाम
युवराज सिंह

1. युवराज सिंह पुत्र कुणाल सिंह नावालिग ववलायत कुणाल सिंह पिता हकीकी 2. कुणाल सिंह पुत्र जयकुमार सिंह साकिन रूधौली कला तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती

तारीख पेशी 30–11–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 30 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्ण वाद संख्या 310 / 2023
पलटू
बनाम
सन्तराम आदि

1. सन्तराम 2. जीतराम 3. विजय 4. प्रेम 5. रामदेव 6. रामफेर पुत्रगण रामअधार निवासीगण ग्राम गौरा तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती 7. भूमि प्रबन्धक समिति अध्यक्ष / ग्रामसभा अध्यक्ष साकिन गौरा ग्राम सभा बड़ा खजुआ पोस्ट कप्तानगंज तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती वर्तमान पता–नगर पंचायत वार्ड नम्बर मोहल्ला अम्बेडकरनगर 8. सरकार उ0प्र0 जरिए कलेक्टर बस्ती

तारीख पेशी 16–10–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 16 माह 10 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

कार्यालय–खण्ड शिक्षा अधिकारी मिठवल, सिद्धार्थनगर

पत्राक / समग्र शि0 / निर्माण / 334–36 / 2026–27 दिनांक–09 / 09 / 2026

नीलामी सूचना

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्रांक / समग्र शि० / निर्माण / 5993–97 / 2026–27 दिनांक 15 सितम्बर 2026 के द्वारा विकास खण्ड मिठवल के कुछ जर्जर विद्यालयों की नीलामी की जानी है जो इस प्रकार है–

विद्यालय का नाम	भवन का प्रकार	मूल्यांकित राशि (रू0 में)
1 प्रा0वि0 अक्सरा माफी	01 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	48729
2 प्रा0वि0 खोजीपुर	01 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	23458
3 कम्पोजिट वि0 परसिया	01 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	49268
4 कम्पोजिट वि0 करमहरिया	01 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष एवं 01 किचेंन	10658
5 कम्पोजिट वि0 पाला	02 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	22693
6 कम्पोजिट वि0 पिड़वा	01 मुख्य भवन एवं 01 किचेंन	11791
7 कम्पोजिट वि0 छितौनी	01 मुख्य भवन	19569
8 कम्पोजिट वि0 रमवापुर दूबे	02 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	168691
9 प्रा0वि0 कटसरया कला	01 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	191474
10 पू0मा0वि0 तेलौरा	02 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष एवं 01 किचेंन	75260
11 पू0मा0वि0 लहरा	01 मुख्य भवन	30694
12 प्रा0वि0 तिगोड़वा	01 मुख्य भवन एवं 02 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष एवं 01 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	66768, 111473, 29859
13 कमपोजिट वि0 बनगड़ोरी	01 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	62706
14 कम्पोजिट वि0 पेड़ार	01 मुख्य भवन	34114
15 प्रा0वि0 सिसई कला	01 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	152388
16 प्रा0वि0 पथरा बाजार	01 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	114879
17 कमपोजिट वि0 डड़वा भइया	01 मुख्य भवन	44454

उक्त नीलामी दिनांक 15 सितम्बर 2026 को दिन में 01 बजे ब्लॉक संसाधन केन्द्र मिठवल पर होगी। नीलामी प्रकिया में बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति / संस्था निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि नकद जमा करने के उपरान्त ही नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति / संस्था के पक्ष में नीलामी की जायेगी जिसे 03 दिनों के अन्दर अवशेष धनराशि जमा करने के उपरान्त 07 दिनों में मलबा हटाना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी ब्लॉक संसाधन केन्द्र मिठवल में चस्पा है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी
मिठवल, सिद्धार्थनगर

दैनिक
भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्मुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com